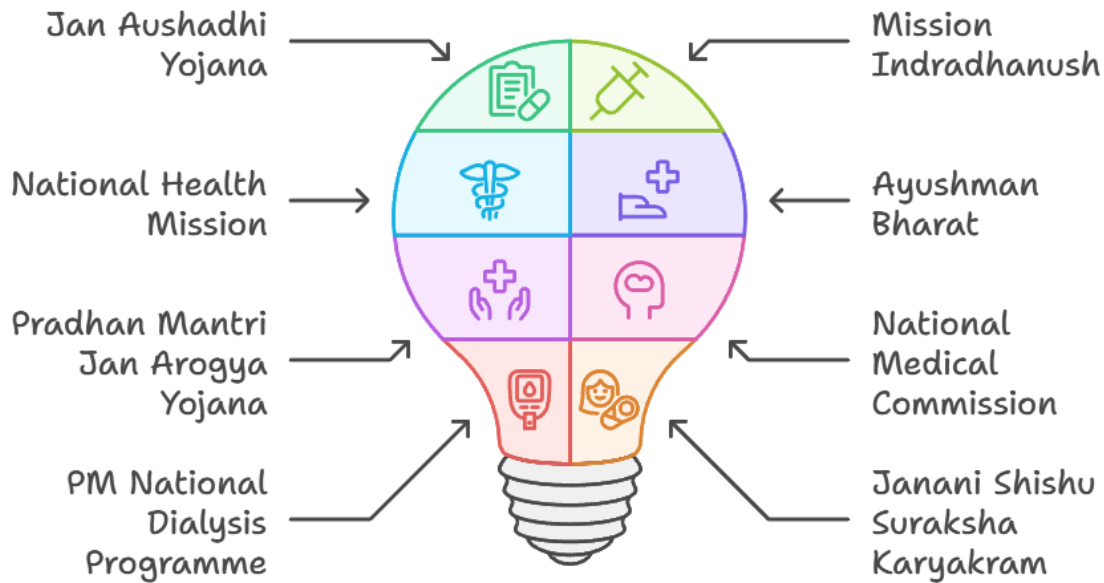


- मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा कलंक, गुणवत्तापूर्ण देखभाल तक सीमिति पहुँच और अपर्याप्त बीमा कवरेज के कारण उपचार में बहुत बड़ी बाधाएँ उत्पन्न होती हैं।
- कोवडि-19 महामारी के कारण विश्व भर में **चिंता और अवसाद के प्रसार में 25% की वृद्धि (WHO)** हुई।
- राष्ट्रीय **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण** से पता चलता है कि **150 मिलियन भारतीयों को मानसिक स्वास्थ्य इंटरवेंशन की आवश्यकता है**, जबकि **प्रति 100,000 जनसंख्या पर केवल 0.75 मनोचिकित्सक हैं।**
- **गैर-संक्रामक रोगों (NCD) में वृद्धि:** भारत के महामारी विज्ञान संक्रमण से पता चलता है कि **गैर-संक्रामक रोगों (NCD) में तीव्र वृद्धि हुई है**, विशेष रूप से मधुमेह, हृदय रोग व कैंसर, जो युवा लोगों को प्रभावित करते हैं जिसके परिणामस्वरूप बीमारी का बोझ दोगुना हो जाता है।
 - **गतहीन जीवनशैली, शहरीकरण और आहार परिवर्तन** के संयोजन के कारण यह प्रवृत्ति बढ़ रही है, जबकि स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियाँ संक्रामक रोग प्रबंधन से लेकर दीर्घकालिक देखभाल मॉडल तक के लिये अनुकूलन करने में संघर्ष कर रही हैं।
 - **NCD एक प्रमुख वैश्विक स्वास्थ्य समस्या है**, जिसके कारण विश्व भर में 74% मौतें होती हैं तथा **भारत में 63% मौतें इसके कारण होती हैं।**
 - भारत में अब **101 मिलियन से अधिक लोग मधुमेह से पीड़ित हैं**, जबकि वर्ष 2019 में यह संख्या 70 मिलियन थी।
- **रोगों का दोहरा बोझ:** भारत को **'रोगों के दोहरे बोझ' का सामना** करना पड़ रहा है, जिसमें संक्रामक और गैर-संक्रामक दोनों प्रकार के रोगों (NCD) से एक साथ नपिटना पड़ रहा है।
 - तपेदिक, डेंगू और मलेरिया जैसी संक्रामक बीमारियाँ, विशेष रूप से ग्रामीण एवं नमिन आय वाले क्षेत्रों में, व्यापक रूप से फैली हुई हैं।
 - कोवडि-19 महामारी के बाद, भारत को उभरते और पुनः उभरते संक्रामक रोगों से नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही **जूनोटिक रोगों और महामारी की तैयारियों के संदर्भ में चिंताएँ बढ़ रही हैं।**
 - भारत में वर्ष 2023 में **H3N2 इन्फ्लुएंजा के 3,000 से अधिक मामले** सामने आए।
 - भारत में, **WHO की PHEIC घोषणा- वर्ष 2022 के बाद से 30 Mpox मामले** सामने आए हैं।
 - अध्ययनों से अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2025 तक **वार्षिक तौर पर कैंसर के मामलों की संख्या में 12.8% की वृद्धि** होगी, जो **लगभग 1.57 मिलियन** होगी।
 - इस बीच, जीवनशैली में बदलाव, शहरीकरण और आहार शैली में बदलाव के कारण मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कैंसर व हृदय संबंधी बीमारियाँ जैसे गैर-संक्रामक रोगों में वृद्धि तेज़ी से हो रही है।
 - यह **दोहरी चुनौती स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों पर दबाव** डालती है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवा संस्थानों को संक्रामक रोगों और दीर्घकालिक देखभाल की आवश्यकता वाली दीर्घकालिक स्थितियों, दोनों का समाधान करना होता है।

//

Recent Government Initiatives to Revamp Healthcare in India



अनेक पहलों के बावजूद भारत प्रभावी स्वास्थ्य सेवा को बनाए रखने में क्यों संघर्ष कर रहा है?

- **खंडति शासन:** भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली **केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर खंडति शासन से ग्रस्त** है, जिसके कारण नीति कार्यान्वयन तथा संसाधन आवंटन में असंगतता होती है।
 - केरल जैसे राज्यों में बेहतर स्वास्थ्य संकेतकों के साथ **सुदृढ़ स्वास्थ्य देखभाल तंत्र** है, जबकि **बिहार जैसे अन्य राज्य पीछे हैं।**
 - क्लिनिकल **क्लिनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट, 2010** का उद्देश्य पूरे भारत में **स्वास्थ्य सेवाओं को मानकीकृत** करना है।
 - हालाँकि इसका **कार्यान्वयन राज्यवार अलग-अलग** होता है, जिसके कारण स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता और वनियमन

प्रवर्तन में अंतर होता है।

- **अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल वित्तपोषण:** महत्त्वाकांक्षी स्वास्थ्य देखभाल पहलों के बावजूद, भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय अभी भी गंभीर रूप से कम बना हुआ है तथा नज्दी क्षेत्र की आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय पर भारी नरिभरता है।
 - आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, भारत में सरकारी स्वास्थ्य व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 1.9% है।
 - भारत में, कुल स्वास्थ्य व्यय में **जेब से किये जाने वाले स्वास्थ्य व्यय (OOP)** का हिस्सा लगभग 62.6% है, जो विश्व में सबसे अधिक है।
- **बुनियादी अवसंरचना और संसाधन असमानताएँ:** स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी अवसंरचना में शहरी-ग्रामीण वभिजन बढ़ता जा रहा है, चकित्सा सुविधाओं, उपकरणों और बुनियादी अवसंरचना के वितरण में महत्त्वपूर्ण असमानताएँ हैं।
 - केवल 11% उप-केंद्र, 13% प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा 16% सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ही भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों को पूरा करते हैं।
 - नीति आयोग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में लगभग 65% अस्पताल बेड लगभग 50% आबादी की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।
- **कार्यबल चुनौतियाँ और प्रतर्भा पलायन:** स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को योग्य पेशवरों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है, जो नरितर प्रतर्भा पलायन एवं असमान वितरण के कारण और भी अधिक गंभीर हो गया है।
 - चकित्सा शक्ति क्षमता, हालाँकि बढ़ रही है, लेकिन गुणवत्ता के मुद्दों से जूझ रही है और स्वास्थ्य सेवा आवश्यकताओं के साथ संरेखित नहीं है। प्रोत्साहन के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में नयिकृतियों आकर्षक नहीं हैं।
 - ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट से पता चलता है कि देश भर में 6,064 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक सर्जनों और बाल रोग विशेषज्ञों की 80% से अधिक कमी है।
- **डेटा प्रबंधन और नगरानी में अंतराल:** डजिटल पहलों के बावजूद, स्वास्थ्य देखभाल डेटा का एकीकरण ठीक से नहीं हो पा रहा है, जिससे साक्ष्य-आधारित नीति-नरिमाण और संसाधन आवंटन में बाधा आ रही है।
 - रयिल टाइम हेल्थ मॉनिटरिंग प्रणालियों की कमी से रोग नगरानी और अनुकरिया क्षमता प्रभावित होती है।
 - गोपनीयता संबंधी चिंताएँ और बुनियादी अवसंरचना की सीमाएँ डजिटल स्वास्थ्य के अंगीकरण की गतिको धीमा कर देती हैं।
 - आयुष्मान भारत डजिटल मशिन के अंगीकरण को बढ़ावा देने के सरकार के पर्यासों के बावजूद, 70% बाज़ार हिस्सेदारी रखने वाले नज्दी क्षेत्र से कुल स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री का केवल 30% ही आया है।
- **नवारक स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान का अभाव:** नवारक स्वास्थ्य देखभाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों के बजाय मुख्य रूप से उपचारात्मक देखभाल पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
 - स्वास्थ्य शक्ति एवं जागरूकता कार्यक्रमों पर अपर्याप्त संसाधन और ध्यान दिये जाते हैं। पर्यावरणीय स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के सामाजिक नरिधारकों पर नीतिगत ध्यान सीमित होता है।
 - नवारक स्वास्थ्य देखभाल पर भारत सरकार का व्यय वर्तमान स्वास्थ्य व्यय (CHE) का केवल 13.55% है।
- **आपूर्ति शृंखला और औषधि संबंधी मुद्दे:** आवश्यक दवाओं और उपकरणों के लगातार स्टॉक खत्म होने के कारण स्वास्थ्य सेवा आपूर्ति शृंखलाएँ अकुशल बनी हुई हैं।
 - आयातित सकरयि दवा सामग्री पर नरिभरता दवा सुरक्षा और लागत को प्रभावित करती है।
 - जेनेरिक दवा कार्यक्रमों को कार्यान्वयन और गुणवत्ता संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
 - भारत अपनी सकरयि फार्मास्युटिकल घटक आवश्यकताओं का लगभग 70% हिस्सा, विशेष रूप से वटामिन और एंटीबायोडकिस, चीन से आयात करता है।

स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- **एकीकृत डजिटल स्वास्थ्य पारस्थितिकी तंत्र:** भारत को एक एकीकृत स्वास्थ्य डेटा अवसंरचना स्थापित करके आयुष्मान भारत डजिटल मशिन के कार्यान्वयन में तेज़ी लानी चाहिये जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर तृतीयक अस्पतालों तक सभी हतिधारकों को जोड़े।
 - इसमें मानकीकृत इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड (EHR), टेलीमेडिसिनि प्लेटफॉर्म और रोग की रयिल टाइम नगरानी प्रणाली शामिल हो सकती है, साथ ही सुदृढ़ डेटा गोपनीयता व सुरक्षा सुनश्चिति की जाएगी।
 - इस प्रणाली को सार्वजनिक और नज्दी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच नरिबाध सूचना आदान-प्रदान की अनुमति देनी चाहिये तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम छोर तक संपर्क सुधार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
 - इसके अतरिकित, ई-संजीवनी जैसे प्लेटफॉर्मों का वसितार कयि जा सकता है और तमलिनाडु से प्रेरित होकर उन्हें सुदृढ़ कयि जा सकता है, जो वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार ई-संजीवनी OPD परामर्श में शीर्ष पर रहा है।
- **प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुदृढ़ीकरण:** स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (HWC) को व्यापक प्राथमिक देखभाल केंद्रों में परवित्ति कयि जाना चाहिये, जो आवश्यक नदिान, टेलीमेडिसिनि सुविधाओं और प्रशिक्षित कर्मियों से लैस हों।
 - नयिमति स्वास्थ्य जाँच, टीकाकरण कार्यक्रम और सामुदायिक स्वास्थ्य शक्ति के माध्यम से नवारक देखभाल एवं शीघ्र रोग पहचान पर ध्यान केंद्रित कयि जाना चाहिये।
 - एक सुदृढ़ रेफरल प्रणाली को प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक देखभाल सुविधाओं को जोड़ना चाहिये, जबकि आशा और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से स्थानीय समुदायों को बेहतर स्वास्थ्य जागरूकता एवं नवारक देखभाल के लिये शामिल कयि जा सकता है।
 - स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के लिये प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन से सेवा की गुणवत्ता और प्रतर्धारण में भी सुधार होगा।
- **सार्वजनिक-नज्दी भागीदारी सुधार:** उच्च गुणवत्ता मानकों को बनाए रखते हुए समान स्वास्थ्य सेवा पहुँच सुनश्चिति करने के लिये नए सार्वजनिक-नज्दी भागीदारी (PPP) मॉडल विकसित किये जाने चाहिये।
 - नज्दी क्षेत्र की भागीदारी के लिये प्रदर्शन मीटरकि, गुणवत्ता मानक औरमूल्य नरिधारण नयित्रण के साथ स्पष्ट नयिमक संरचना को लागू कयि जाना चाहिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन-से 'राष्ट्रीय पोषण मशिन (नेशनल न्यूट्रशिन मशिन)' के उद्देश्य हैं? (2017)

1. गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण से संबंधी जागरूकता उत्पन्न करना ।
2. छोटे बच्चों, कशोरियों तथा महिलाओं में रक्ताल्पता की घटना को कम करना ।
3. बाजरा, मोटा अनाज तथा अपरष्कृत चावल के उपभोग को बढ़ाना ।
4. मुरगी के अंडों के उपभोग को बढ़ाना ।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1,2 और 3
- (c) केवल 1,2 और 4
- (d) केवल 3 और 4

उत्तर: (a)

??????:

Q. "एक कल्याणकारी राज्य की नैतिक अनविर्यता के अलावा, प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना धारणीय वकिस की एक आवश्यक पूर्व शर्त है ।" वश्लेषण कीजिये । (2021)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/bridging-gaps-in-india-s-health-system>

